

Hindustan Times- 08- July-2022



A breach in a patch of the Kutch Branch Canal project. HT PHOTO

Kutch canal patch stops Narmada in its tracks

Maulik Pathak

letters@hindustantimes.com

AHMEDABAD: Hours after successfully taking the waters of Narmada to Modh Kuva, the village at the tail-end of the Kutch Branch Canal (KBC), the authorities had to stop flow after a patch in path breached on Thursday.

"We were conducting trials for the last week, and for the first time the waters reached Modh Kuva late on Wednesday night. The 750 kms flow from the Sardar Sarovar dam site is the longest in the country for a man-made canal. In one part, the canal developed a breach, and we plan to repair it and restart the trials in the next 2-3 days. The trial aimed to look out for any issues and address them immediately," J P Gupta, chairman of Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd (SSNNL) said.

KBC is part of the ambitious Sardar Sarovar project, with

more than 60,000 kms of the canal network.

Gupta said that preliminary investigation showed that the place where the pipeline was damaged had some issues in the joint area with some private pipelines running beneath.

The ₹6,493 crore KBC project aims to bring 102,200 hectares of land under irrigation and provide drinking water to 906 villages in the semi-arid region of Kutch.

The work for more than 200 kms on KCB was completed about four years ago, and the remaining stretch was stuck due to land acquisition issues, said people close to developments.

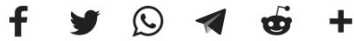
The waters reached Modh Kuva around 1 am, four hours before the breach was found at Bidada village said an official.

"The patch that got damaged was completed in 2016. The breach was 10 meters deep," the official said.

The Hans- 08- July-2022

Flood warning as KRS reservoir eight feet short of FTL

Hans News Service | 8 July 2022 12:09 AM IST



The Krishnarajasagara reservoir which is receiving more than 35,000 cusecs of inflow due to a heavy rain in its catchment area is just eight feet short of FTL (full tank level).

ADVERTISEMENT

Mandya: The Krishnarajasagara reservoir which is receiving more than 35,000 cusecs of inflow due to a heavy rain in its catchment area is just eight feet short of FTL (full tank level). The Cauvery Neeravari Nigam Limited (CNNL) authorities on Wednesday evening issued a flood warning stating that excess water would be released anytime as the dam is nearing its full capacity.

They said the dam's catchment area is receiving heavy rainfall leading to the spike in the inflow.

According to irrigation authorities, the dam level reached 116.7ft on Thursday against the maximum level of 124.8 ft.

The dam recorded an inflow of 35,923 cusecs while a total of 3,575 cusecs of water is being let into irrigation canals and rivers. In the corresponding year, the water level stood at 90.30 ft with an inflow rate of 1,591 cusecs.

Meanwhile, leaders of farmers are demanding that the irrigation authorities take steps to fill the village tanks in Nagamangala, Pandavapura and Maddur taluks by releasing water from KRS and Hemavati reservoirs.

In a first of its kind, Water Resources Department organised a meeting of elected representatives and stakeholders on implementation of Emergency Action Plan for KRS, Kabini, Harangi and Chikkahole reservoirs.

CNNL along with Water Resources Department is holding a one-day stakeholders' consultation meeting on Friday. The elected representatives from Mysuru, Mandya, Chamara Nagar, Hassan, Kodagu and Ramanagar will be taking part in the programme.

It will discuss the impact and role of stakeholders in the management of floods at river banks. Water Resources Minister Govind M Karajol will inaugurate it. Central Water Commission, New Delhi, Director Pramodh Narayan, Chief Engineer Gulshan Raj, and Madhav, Nodal officer of DRIP project, Bengaluru will participate as resource persons. Deputy commissioners and Zilla Panchayat CEOs will also be taking part

Rashtriya Sahara- 08- July-2022

जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के प्रयास तेज

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं सेंट्रल नोडल ऑफिसर विजय मित्तल व उनकी टीम ने वृहस्पतिवार को गौतमबुद्धनगर का निरीक्षण किया। नोएडा व ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कई स्थानों का भ्रमण करने के बाद विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के बैठक कर जल शक्ति अभियान से संबंधित गतिविधियों को निर्धारित मानक एवं समय के भीतर पूरा करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। विजय मित्तल ने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रैन सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिसके माध्यम से ग्राउंड वाटर को संरक्षित करने एवं पानी के दुरुपयोग को रोकना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 75 तालाव अमृत सरोवर बनाए जाने के उद्देश्य से चयनित किए गए हैं, चयनित सभी तालावों का काम नवम्बर तक आवश्यक रूप से पूरा करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। जल शक्ति अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने

कार्यक्रमों का
निरीक्षण करने पहुंचे
संयुक्त सचिव

के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाएं, ताकि ग्राउंड वाटर को संरक्षित करने के साथ-साथ पानी के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में भी जनपद में अच्छे प्रयास सुनिश्चित हो सके। जल शक्ति अभियान से जुड़े कार्यक्रमों की गहन समीक्षा में पाया कि सभी प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के द्वारा अच्छे प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के लिए फेस के रूप में काम करता है। जनपद में जो अच्छे कार्यक्रम जल शक्ति अभियान को लेकर पूर्ण किए जा रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी बनाकर केंद्र सरकार के पोर्टल पर पोस्ट की जाए ताकि अन्य प्रदेश एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के मॉडल के आधार पर अपने-अपने जनपदों में इस अभियान को लेकर गतिविधियां संचालित कर सकें। इस मौके पर सहायक अभियंता लघु सिंचाई हिमांशु गौतम ने पीपीटी के माध्यम से संयुक्त सचिव को जनपद में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में डीएफओ पीके श्रीवास्तव ने जनपद में संचालित किए जा रहे पौधरोपण के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा कहा कि वर्तमान तक 90 फीसद से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है।

Rajasthan Patrika- 08- July-2022

नीति-नवाचार: जिला या तहसील स्तर पर ज्यादा बड़े खतरों की पहचान, आकलन और अनुमान होना चाहिए बाढ़ के जोखिम वाले राज्यों में हो पहले से तैयारी

असम में आई बाढ़ ने राज्य के 80 फीसदी से ज्यादा जिलों को जलमग्न कर दिया। इसी तरह बीते साल नवंबर में असामान्य बारिश ने चेन्नई और आसपास के जिलों को डुबो दिया था। ये स्पष्ट सबूत हैं कि कैसे जलवायु संबंधी जोखिम वाले राज्यों को बदलती जलवायु के कारण खतरों का सामना पड़ रहा है। 2022 की शुरुआत में आई इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि जलवायु संबंधी घटनाओं की सीमाएं टूटने जा रही हैं, क्योंकि अगले कुछ दशकों में औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री से ज्यादा रहने की आशंका बढ़ती जा रही है। भारत के लिए इसका मतलब है कि भीषण गर्मी पड़ने और लू चलने की घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे कृषि उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ, चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी मौसम की चरम घटनाओं के कारण जल और लावा जन्तु बीमारियां व पलायन दर भी बढ़ सकती हैं।

वर्ष 2021 में प्रकाशित काउंसिल ऑन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) का क्लाइमेट क्लेरेरेबिलिटी इंडेक्स बताता है कि असम, बिहार, उत्तराखंड और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण बाढ़ के जोखिम बहुत ज्यादा हैं। भारत के 60 फीसदी से ज्यादा जिलों में जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के खतरे मौजूद हैं। असम जैसे बाढ़ के



अबिनाश मोहंती
प्रोग्राम लीड, काउंसिल ऑन
एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड
वॉटर (सीईईडब्ल्यू)
@patrika.com

जोखिम वाले राज्यों की बात करें तो 10 में से लगभग 8 लोगों के सामने भीषण बाढ़ की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के खतरे वाले राज्य हर साल अपनी प्राकृतिक बनावट में तेज रफ्तार से बदलाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे संवेदनशील राज्यों में 65 प्रतिशत से ज्यादा प्राकृतिक बनावटों को मानवीय गतिविधियों के कारण नुकसान पहुंच रहा है। यह समस्या प्राकृतिक बनावट की क्लाइमेट प्रूफिंग न होने की कमी के साथ मिलकर राज्यों में बाढ़ का जोखिम बढ़ा रही है। ऐसे में तीन कदम बाढ़ के जोखिम वाले राज्यों में समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित कर सकते हैं।

पहला, ज्यादा जोखिम वाले असम जैसे राज्यों को जिला या तहसील स्तर पर ज्यादा बड़े खतरों की पहचान, आकलन और अनुमान करना चाहिए। क्लाइमेट रिस्क एटलस का उपयोग करते हुए जलवायु जोखिमों की जटिलता और उसके अनिश्चिततापूर्ण प्रभावों की जानकारी

राहत-केंद्रित दृष्टिकोण की जगह प्रतिक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर जोखिम वाले राज्यों में विभिन्न समुदायों व अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु से जुड़े खतरों का सामना करने में सक्षम जरूर बनाया जा सकता है।

जुटानी चाहिए। यह बाढ़ जैसी चरम जलवायु घटनाओं के लिए बेहतर तैयारियों को सुनिश्चित करेगा, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्य योजनाओं का हिस्सा हैं। ऐसे उपाय राज्य के प्रशासन और कमजोर समुदायों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा, ऐसे राज्यों को अपने अलीवर्निंग सिस्टम (प्रारंभिक चेतावनी तंत्र) में बदलाव करना चाहिए, ताकि सामान्य या निरर्थक पूर्वानुमानों की जगह पर प्रभाव आधारित पूर्वानुमानों को लाया जा सके।

दूसरा, जलवायु संबंधी जोखिम वाले राज्यों को मैंग्रोव वनों, आर्द्रभूमियों और जंगलों जैसे प्राकृतिक इको-सिस्टम को दोबारा खड़ा करके पर्यावरणीय क्षमता बढ़ानी चाहिए। यह राज्य की नीतिगत जरूरत बन जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रकृति अनुकूल सफल उपायों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। इनमें आर्द्रभूमियों और जल प्रबंधन की पारंपरिक संरचनाओं में बायो-डाइक, खस-घास से बने तटबंध बनाने, और रेत के टीलों को सुधारने जैसे काम

शामिल हैं। यह न केवल भीषण बाढ़ के झटकों को रोकने, बल्कि नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकता है। यह इको-टूरिज्म और एकीकृत कृषि पद्धति जैसे नए आर्थिक अवसरों को भी जन्म दे सकता है।

तीसरा, चाहे असम हो या तमिलनाडु, बाढ़ प्रबंधन प्रमुख शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की क्लाइमेट-प्रूफिंग की मांग करता है। उदाहरण के लिए, असम अपने प्रमुख शहरी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा का निवेश करना चाहता है। यह काम इमारतों, सड़कों और अन्य शहरी निर्माण इत्यादि (ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर) और नदी, नहर, तालाब, बाढ़ के मैदान व जल शोधन इत्यादि (ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर) को आपस में जोड़कर किया जा सकता है। यह बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के साथ, सूक्ष्म-जलवायु परिवर्तन को रोकने और बुनियादी ढांचे की जीवन अवधि बढ़ाने का दोहरा लाभ दे सकता है। इसे उत्तराखंड, बिहार और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं।

जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बात अब पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है कि आने वाले वर्षों में जलवायु संबंधी भीषण घटनाएं टाली नहीं जा सकती हैं, पर राहत-केंद्रित दृष्टिकोण की जगह प्रतिक्रिया-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर जोखिम वाले राज्यों में विभिन्न समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु से जुड़े खतरों का सामना करने में सक्षम जरूर बनाया जा सकता है।